संसद में सुशील कुमार मोदी

राज्य सभा का 255वाँ सत्र

(29 नवम्बर से 22 दिसम्बर 2021)

महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर भाषण एवं हस्तक्षेप

विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख

अपने मन में एक लक्ष्य लिए
मंज़िल अपनी प्रत्यक्ष लिए
हम तोड़ रहे हैं जंजीरें
हम बदल रहे हैं तस्वीरें
ये नवयुग है, नव भारत है
खुद लिखेंगे अपनी तक़दीरें
हम निकल पड़े हैं प्रण करके
अपना तन-मन अर्पण करके
जिद है एक सूर्य उगाना है
अम्बर से ऊँचा जाना है
एक भारत नया बनाना है
एक भारत नया बनाना है

-नरेन्द्र मोदी

अनुक्रमणिका

1.	**2nd Supplementary** बजट 2020-21 पर भाषण	1-9
2.	आधार को वोटर आई.डी. कार्ड से जोड़ने सम्बन्धी बिल	10-14
3.	**CBI** और **CVC** के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाए जाने सम्बन्धी बिल	15-19
4.	केन्द्रीय विद्यालयों में **MP** कोटा समाप्त करने हेतु	20-21
5.	सोशल मीडिया द्वारा फेक न्यूज को हटाने पर पर्याप्त खर्च करने के सम्बन्ध में	22-23
6.	ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने हेतु	24-25
7.	**Work From Home** हेतु कानून बनाने के सम्बन्ध में	26
8.	**Cryptocurrency** के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर	27-28

विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख

1.	**India's Inflation Story**	29-31
2.	**Gaming Versus Gambling**	32-34
3.	**Tyranny of the Opposition**	35-36
4.	**Whither Cryptocurrency**	37-39

The Appropriation (No.5) Bill, 2021
पर
राज्य सभा में भाषण

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उप-सभापति महोदय, मैं Second batch of Supplementary Demands जो हमारे यहाँ एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में आया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन में प्राइस राइज पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन यह पूरा विषय प्राइस राइज से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि विपक्ष हम पर जो आरोप लगाता है कि भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण मूल्यवृद्धि हो रही है, मैं उन सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह मूल्यवृद्धि पूरी दुनिया का फिनॉमिना बन चुकी है। Post-pandemic, Inflation has started to run and even in a country like America, since the last 39 years, the highest rate of inflation at 6.8 per cent has occurred in America in this month only. यानी अमेरिका जैसे देश में 39 साल के बाद पहली बार महंगाई का रेट 6.8 परसेंट पर पहुंच गया है। यूरोपियन यूनियन के अन्दर यह 4. 1परसेंट है, जो 13 साल के भीतर हाइएस्ट है और 13 सालों में यह डबल हो गया है। यूनाइटेड किंगडम में यह 4.2 परसेंट है, ब्राजील में 10.67 परसेन्ट है, तुर्की में 20 परसेंट है, अर्जेन्टीना में 50 परसेंट है., रशिया में 8.1 परसेंट है।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद अर्थव्यवस्था को जिस तरह से नियंत्रित किया है, उसी का परिणाम है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन नियंत्रण में है। इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या हैं? पूरी दुनिया के अन्दर चिप्स की शॉर्टेज हो गई। आपने अखबारों में देखा होगा कि जो मोटर व्हीकल्स हैं, उनकी बिक्री कम हो गई, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, कोरोना और बाकी कारणों से उनकी सप्लाई से शॉर्टेज आ गई। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोटर व्हीकल्स के साथ-साथ Containers की शॉर्टेज हो गई, शिपमेन्ट्स की शॉर्टेज हो गई है। मेटल्स, मिनरल्स, क्रूड ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स इन सारी चीजों को शॉर्टेज हो गई है।

महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी है, हम आइसोलेशन में नहीं हैं। अगर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता है। India is forced to import

that international inflation. अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लेशन को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, as India is linked with global economy and relies on global regional value chain for its economic operation.

महोदय, 2008 में इस देश में किसकी सरकार थी – कांग्रेस की सरकार थी। जब ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस हुआ था, उस समय उन्होंने इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया, जबकि 2008 में न तो लॉकडाउन था और न कोई कोरोना था और उस समय महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम लोगों ने कोरोना के बावजूद डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनाकर इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने का काम किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जो लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाये, वे लोग हम पर आरोप लगाते हैं।

महोदय, इन्फ्लेशन बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं – प्रथम अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके दामों में वृद्धि और दूसरा एडिबल ऑयल है। अपनी आवश्यकता का 83 परसेंट से ज्यादा पेट्रोलियम पोडक्ट्स हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और खाद्य तेल एडिबल ऑयल, उसे 60 परसेन्ट से ज्यादा आयात करना पड़ता है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : महोदय, Petroleum का price जहाँ डेढ़ साल पहले 20 dollars per barrel था, वह बढ़ कर 80 dollars per barrel पर पहुँच गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि जो petroleum exporting countries हैं, उन्होंने जान-बूझ कर इसकी Supply को कम कर दिया, ताकि विश्व के बाजार में petroleum के price में और वृद्धि हो सके। इतना ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर LPG के price में भी 238 परसेंट की वृद्धि हो गयी। चूँकि आयात करते समय हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, हमारा जो exchange rate है, वह जहाँ 2014 में 60 rupees per dollar था, वह बढ़ कर 75 rupees per dollar पर पहुँच गया। इन सारी चीजों का परिणाम यह हुआ कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के मूल्य में अगर एक डॉलर की वृद्धि होती है, तो उसके कारण भारत में 50 पैसा प्रति लीटर की वृद्धि करनी पड़ती है।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को नीचे लाने के लिए 10 रूपये प्रति लीटर पेट्रोल और 5

रूपये प्रति लीटर डीजल में कटौती करने का निर्णय लिया। बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में भारी कटौती की, लेकिन केरल में किसकी सरकार हैं, सीपीएम की सरकार है। उसने वैट के अन्दर कोई कटौती नहीं की। कांग्रेस झारखण्ड और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है – महाराष्ट्र और झारखंड में – वहाँ उन्होंने पेट्रोल और डीजल के वैट में कोई कटौती नहीं की। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग वैल में आकर हल्ला करते हैं। मैं ममता बनर्जी जी से जानना चाहता हूँ कि जब बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के वैट में कटौती कर दी, तो बंगाल ने कटौती क्यों नहीं की? बगल के बिहार ने इसमें कटौती कर दी, लेकिन अर्जुन मुंडा जी यहाँ बैठे हैं, इनके राज्य झारखंड में, बगल के बंगाल में, तमिलनाडु में डीएम की सरकार है, उन्होंने इसमें कोई कटौती नहीं की। आज भी 7 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने पेट्रॉल और डीजल के मूल्य में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की। आज देश में सबसे ज्यादा वैट अगर किसी एक राज्य में है, तो उसका नाम महाराष्ट्र है, वहाँ पेट्रॉल पर 39 परसेंट और डीजल पर 28 परसेंट वैट लग रहा हैं। केरल में सीपीएम की सरकार है, वहाँ पेट्रॉल पर 30 परसेंट वैट है, बंगाल में पेट्रोल पर 29 परसेंट वैट है, तेलंगाना में 33 परसेंट और तमिलनाडु में 33 परसेंट वैट है।

महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पेट्रॉल और डीजल के मामले में इतनी बड़ी कटौती की, तो इसका परिणाम क्या हुआ – हमें हर महीने में 8,689 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर हम यह कटौती नहीं करते तो the Government of India would have gained Rs. 8,689 crores per month. The Government of India is losing revenue of Rs. 1.04 lakh crores in a year! लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को राहत मिले, लोगों को सुविधा मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। उसने दिखावे के लिए वैट में केवल 90 पैसे की कटौती की।

महोदय, भारत सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमारे पास पेट्रोलियम का Strategic reserve है। हमने तय किया कि हमारे पास जो Strategic reserve है, उससे हम 5 मिलियन बैरल, यानी 50 लाख बैरल release करेंगे। हमने विशाखापत्तनम, मेंगलुरू और पाडुर में strategic reserve इसलिए बनाकर रखा है ... (व्यवधान)... 1973–74 में तेल का संकट हुआ था। जब अटल जी प्रधान मंत्री बने तब यह निर्णय हुआ कि हम अपने तेल

का भंडार रखेंगे ताकि अगर 64 दिनों तक तेल का संकट हुआ, तब भी हम उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए हमनें strategic reserve बनाकर रखा। पहली बार भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम Strategic reserve से 50 लाख बैरल तेल release करेंगे। यह हम अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के साथ मिल कर करेंगे, ताकि दुनिया के अन्दर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में कमी आ सके।

महोदय, जो हम आरोप लगाते हैं कि आपके समय में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने oil bonds issue किये थे और कहा कि हम लोगों को लाभ दे रहे हैं, पेट्रॉल और डीजल के दामों में कटौती कर रहे हैं।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : महोदय, इन लोगों ने 1,30,000 करोड का oil bond जारी कर दिया, जिसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ेगा। इन लोगों ने दाम में कटौती करके वाहवाही लूटी और 1,30,000 करोड़ रूपये का oil bond इश्यू कर दिया। हमें 2015-16 से 10,000 करोड़ रूपए इसके ब्याज के रूप में देने पड़ रहे है।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो पेट्रोल पर पाँच और डीजल पर दस रूपए कम किये हैं, उसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा।

महोदय, मूल्य वृद्धि का एक दूसरा बड़ा कारण edible oil है। हम 60 परसेंट से ज्यादा खाद्य तेल दुनिया के बाजार से आयात करते हैं। हम मलेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया आदि देशों से crude और refined oil आयात करते हैं। चूँकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई, इसलिए मजबूरन भारत में भी खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि हुई। पूरे देश में खाद्य तेल की जो खपत है, उसमें palm oil की खपत 45 परसेंट है, सोया की 20 परसेंट है, सरसों के तेल की खपत 10 परसेंट है और बाकी मूँगफली, सूरजमुखी तथा अन्य तेल की खपत है।

महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फरवरी से अभी तक खाद्य तेल की crude और refined oil की इम्पोर्ट ड्यूटी में पाँच बार कटौती की है। अभी अक्टूबर, 2021 में import duty on crude palm/sunflower oil को घटा कर जीरो प्रतिशत कर दिया

गया है। साथ हीं palm, sunflower और soya के refined oil पर जो एग्रीकल्चर सेस लगता था, उसको भी घटाने का काम किया गया है। भारत सरकार ने सात चीजों की derivative market में जो forward trading होती है, उस पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही साथ, कोई भी व्यापारी दो माह से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेगा।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। जिन लोगों ने 60 साल तक राज किया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हमें खाद्य तेल क्यों आयात करना पड़ रहा है? हमने तिलहन की उपज को बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? हमारी सरकार में आदरणीय प्रधान मंत्री जी की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अगले पाँच साल के लिए 11,040 करोड़ रूपए का National Mission on Edible Oil बनाया जाएगा। हम अगले पाँच साल में 11,040 करोड़ रूपये खर्च करेंगे ताकि तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। palm oil का जो acreage 6.5 लाख हेक्टेयर है, उसके उत्पादन का जो क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हमने यह तय किया है कि crude palm के उत्पादन को 2025-26 तक 11.2 lakh tones और 2029-30 तक 28 lakh tonnes तक बढ़ाएँगे।

भारत सरकार ने यह भी विचार किया कि जो किसान तिलहन पैदा करेंगे, अगर मार्केट fluctuate करती है, तो Centre will pay the difference to palm oil farmers. इस तरह से किसान को प्राइस का assurance दिया गया है। अगर बाजार दर और उसके लागत मूल्य में अंतर होगा, तो भारत सरकार फार्मर्स को viability, gap funding के द्वारा क्षतिपूर्ति करने का काम करेगी।

महोदय, इन सबका परिणाम यह हुआ है कि पिछले दो महीने के भीतर groundnut oil, mustard oil, soybean, sunflower, palm oil इन सब के मूल्य में भारी कमी आई है। आज दाल की कीमत भी नियंत्रण में है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : जब दलहन का संकट पैदा हुआ, तब हमारी सरकार ने दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, आगे आने वाले दिनों में दाल, जिसे हमें बर्मा और दुनिया के बाकी देशों से आयात करना पड़ता है, तो दल्हन और तिलहन और ये जो खाद्य तेल हैं, जो pulses हैं, इनके मामले में भारत बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो पाएगा।

उप–सभापति महोदय, इस Supplementary Budget में एयर इंडिया के लिए 62,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, Rs.62,057 crores for influsion into Air India Assets Holding. महोदय, यह महाराजा इतना गरीब कैसे हो गया? एयर इंडिया एक जमाने में नवरत्न था। वह नवरत्न इतना गरीब हो गया है कि आज इसे bail out करना पड़ रहा है। अगर आज एयर इंडिया 70,000 करोड़ रूपये से ज्यादा से ज्यादा के कर्ज में डूबा है, तो उसका कारण यह काँग्रेस है, जिसने अपने दस साल के शासनकाल में एयर इंडिया और इंडिया एयरलाइंस को यहाँ तक पहुंचा दिया। 2006–07 के अंदर एयर इंडिया का घाटा 541 करोड़ था और इंडियन एयरलाइंस का घाटा 230 करोड़ था। To stem the rising losses, the UPA Government on July 15, 2007, decided to merge Air India and Indian Airlines. इन्होंने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया और मर्ज करने का परिणाम यह हुआ – the merger was a gross mistake as ther was no synergies; resources, aircraft, men, materials and machines remained divided. Ther merger simply magnified problems like excess manpower. Mr. Vice-Chairman, Sir, due to the policies of the UPA Government vis-a-vismerged entity, an arbitrary decision, पहले ही साल में एयरलाइंस का घाटा बढ़कर 2,226 करोड़ तक पहुंच गया। महोदय, 2007 से लेकर 2009 के बीच में घाटा बढ़कर 7,200 करोड़ तक पहुंच गया।

उप–सभापति महोदय, यूपीए की सरकार में पहले निर्णय लिया गया था कि दस एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाने हैं। लेकिन इन्होंने खरीदें कितने? इन्होंने 111 एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए। जो एयरलाइंस घण्टे में चल रही थी और केवल दस नए हवाई जहाज खरीदने थे, तो आपने किसके कहने पर 111 हवाई जहाज खरीदे?

महोदय, विनोद राय, जो सीएजी थे, उनकी किताब आई है – 'Not Just an Acccountant.' wherein Shri Vinod Rai describes how Air India's Board of Directors had orginally placed a Letter of Intent on airbus for only 10 aircraft. विनोद राय जी ने अपने पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि केवल दस एयरक्राफ्ट्स खरीदने का निर्णय लिया था, but the Air India Board was nudged to change the order to a Boeing and increase the order from 10 to 111! महोदय, आखिर क्या कारण था कि दस एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाने थे, लेकिन 111 एयरक्राफ्ट्स खरीद

लिए? प्लानिंग कमीशन ने भी इस पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज की थी। महोदय, एक बड़े देश के राष्ट्रपति का भारत भारत में दौरा होने वाला था और उस देश को खुश करने के लिए, क्योंकि वे वायुयान उस देश में बनते थे, इसलिए दस के बजाय 111 एयरक्राफ्ट्स खरीद लिए गए – एयर इंडिया के loss में जाने का यह बहुत बड़ा कारण था।

महोदय, मैं टाटा कंपनी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 70,000 करोड़ के डूबते हुए जहाज को खरीदने का फैसला किया है । काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके संबंध में सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए जो मेडिकल बेनिफिट है, वह लगातार जारी रहेगा तथा जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वे एक साल तक काम करेंगे और अगर बाद में चाहेंगे, तो वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ सकते हैं। महोदय, हमने एयर इंडिया के पैकेज के द्वारा महाराजा को फिर से महाराजा बनाने का प्रयास किया है।

इसके साथ ही, हमने रेलवे के लिए 20,000 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया है। रेलवे में जो सुधार हुआ है, उसी का परिणाम है कि during the last five years, that is, from 2016-17 to 2020-21, number of train accidents has shown a continuously decreasing trend.

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : आजकल अखबारों में कहीं भी रेल दुर्घटना का समाचार दिखाई नही पड़ता है। वर्ष 2016–17 में 104 ट्रेन दुर्घटनाएँ हुई थी, जबकि वर्ष 2020–21 में यह संख्या घटकर केवल 22 रह गई। यह है नरेन्द्र मोदी जी की सरकार। रेलवे को जनरल बजट के साथ merge कर दिया गया। हमने रेलवे की सुरक्षा के लिए जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि जहाँ वर्ष 2016–17 में 104 रेल दुर्घटनाएँ हुई थीं, वे घटकर 22 पर पहुँच गई।

महोदय, आपको पता है कि पिछले दो वर्षों में रेल दुर्घटना में एक आदमी की भी मौत नहीं हुई है, अन्यथा कोई साल नहीं था जब 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग रेल दुर्घटना में नहीं मारे जाते थे। हाँ, कुछ लोग कह सकते है कि वर्ष 2020–21 में कोरोना में ट्रेन चली नहीं, तो लोगों की मृत्यु नहीं हुई, परन्तु In 2019-20 when there was no Crona, there was no pandemic, not a single passenger died because of rail accident. यह है नरेन्द्र मोदी की सरकार।

महोदय, इस बजह में Rs. 12,000 crore has been given for a major upgrade of stations and Rs. 11,000 crore for covering the cost of 100 train sets. नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक और ऐतिहासिक काम किया है। जो ट्रेनें चलती थी, ये डीजल पर चलती थीं, लेकिन सरकार ने यह तय किया कि हम रेल का विद्युतीकरण करेंगे, ताकि डीजल की बचत हो और पर्यावरण भी प्रदूषित न हो। as on 1st April, 2021, out of 64,689 board gauge route kilometer -- उसका 71 परसेंट हमने electrification कर दिया है। अब बहुत जल्द 100 प्रतिशत रेलवे के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। This has resulted in reduction in emission of 9.99 lakh tone of carbon dioxide. यानी करीब 10 लाख टन Carbon dioxide को हमने रिलीज होने से बचा लिया, जो वायुमंडल में जाकर प्रदूषित करता। We were able to save 10 lakh tonne of carbon dioxide in the year 2019-20. वर्ष 2021-22, we have provided Rs. 1.55.000 crore. हमने सब्सिडी के लिए प्रावधान किया है, ताकि किसानों को ऊँचे मूल्य पर यूरिया और डीएपी न खरीदना पड़े। जो लोग किसानों को लेकर आंदोलन करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या यूरिया और डीएपी का दाम बढ़ा? क्या लोगों को यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है? Global fertilizer prices surged roughly 200 per cent. जो फर्टिलाइज़र है, उसके दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 परसेंट की वृद्धि हुई। उसका कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयला और नैचुरल गैस, उसके निर्माण के दो मुख्य आधार थे, उनके निर्यात पर चाइना और रशिया ने प्रतिबंध लगा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर फर्टिलाइजर के दाम में काफी वृद्धि हो गई।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (CONTD.) : India raises the subsidy to protect farmers from price shocks. Retail price of a tonne of DAP in India is less than half the global price. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की जितनी कीमत है, भारत में उससे आधी कीमत पर हम किसानों को दे रहे हैं। पहले हम 15 ट्रेन्स से फर्टिलाइजर पहुंचा रहे थे। अब हर राज्य के अंदर 30 ट्रेन्स से फर्टिलाइजर को पहुंचाया जा रहा हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई संकट न हो सके।

महोदय, In November, 2020, Under the Atmanirbhar Bharat package, the Government announced additional allocation of Rs. 65,000 crore in 2021 for fertilizer subsidy. As a result, the allocation for 2021 increased from Rs. 71,039 crore to Rs. 1,33,000 crore at the revised stage.

महोदय, किसी भी अर्थव्यवस्था को नापने के लिए 22 high frequency indicators हैं जिसमे से 19 मानकों को हमने 2019 के लेबल को पार कर लिया है । अभी स्टील, domestic auto sale and air passenger traffic केवल तीन मानक है जहाँ हम पीछे हैं। हमें स्टील भी आयात करना पड़ता है। आज semi conductor crisis के कारण गाड़ियों के उत्पादन में छह-छह महीने का समय लग रहा है। अगर इन तीन मानकों को छोड़ दें, तो 22 में से 19 ऐसे मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, जिनमें 2019 का जो लेवल था, उसको हमने क्रास कर लिया है - मैं उन मानकों का नाम बताना चाहूंगा - UPI, Google, Mobility, merchant imports, e-way bill volume, merchant exports, coal production, rail freight traffic, fertilizer sale, PMI services, power consumption, PMI manufacturing, tractor sales, cement production, port cargo traffic, core industries, index of industrial production, fuel consumption, इन 19 मानकों पर कोविड के पहले हमारी जो स्थिति थी, हमने उसको पार कर लिया है। अभी भी स्टील, air passenger traffic और domestic auto sale ये तीन मानक बचे हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं।

महोदय, यह भारत की सरकार है, यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है - जहां पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वहीं हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखाया है। चिदम्बरम साहब ने ब्यान दिया था कि नरेन्द्र मोदी जी, नोट छापिए, आपके पास प्रिंटिंग मसीन है, जितने नोट छाप सकते हैं, छापिए और लोगों को दीजिए। अगर हमने उनकी बात को मान लिया होता, तो आज हमारा inflation का rate 15-20 परसेंट तक पहुंच गया होता। अमेरिका ने लोगों को stimulus package बांट दिये, तो आज वह 39 साल के highest inflation rate पर पहुंच गया। हमने कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला किया और अर्थव्यवस्था को भी ठीक दिशा देने का काम किया है।

महोदय, मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 का वर्ष भारत के लिए और शुभ होगा। महोदय, वर्ष 2019 के पहले की जो स्थिति थी, हम 2022-23 के अंदर भारत को उस स्थिति में पहुंचाने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

◈◈◈

The Election Laws (Amemdment) Bill, 2021
पर
राज्य सभा में दिया गया भाषण
(आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने सम्बंधी बिल)

MR DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shri Shushil Kumar Modi.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ... (व्यवधान) ... महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिन लोगों में पार्लियामेंटरी स्टैंडिग कमिटी में यह माँग की, यह समर्थन किया कि 'आधार' के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाए, आज वही लोग वैल में आकार इसका विरोध कर रहे हैं। ... (व्यवधान) .. . श्री सुखेन्दु शेखर राय, ये टीएमसी के मेम्बर है। ... (व्यवधान) ... उपसभापति महोदय, ये उस कमेटी में शामिल थे। ... (व्यवधान) ... एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी, जिसके चेयरमैन श्री भूपेन्द्र यादव थे, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से यह रिकमंड किया और कहा कि 'आधार' के साथ वोटर आईडी को लिंक किया जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : उपसभापति महोदय, वर्ष 2020-21 की Demands for Grants की जो 101st Report है, जिसको सदन के फ्लोर पर lay किया गया, मैं उसकी recommendation को पढ़ना चाहूँगा। ... (व्यवधान) ... it says, "The Committee understands that free and fair elections is the bedrock of democracy and the latter is a basic feature of the Constitution. An error free electoral roll is sine qua non of a free and fair election. The Commtee has been advocating linkage of unique Aadhar ID Card number with voter I-Card which would steamline alterations in EPIC during ordinary change of residence by the elections. The incidence of multiple entry could also be eliminated which is required in participative democracy. The Committee, therefore, recommends that the Government may undertake appropriate actions for the purpose of linking unique Aadhar Card number with Voter ID Card to purify the electoral roll which is in larger interest of democratic

polity." ... (interruptions) ... उपसभापति, महोदय, इस सदन के अंदर जिस पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट lay की गई है, उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। ... (व्यवधान) ... उसकी रिपोर्ट की यह अनुशंसा हैं। ... (व्यवधान) ...उसके रिपोर्ट की यह अनुसंशा है..... (व्यवधान) ...

महोदय, वर्ष 2021-22 की Demands for Grants की 107th Report इस सदन के पटल पर रखी गई, उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। ... (व्यवधान) ... It says, "The committee reiterates its recomendation that the Government may undertake appropriate action for the purpose of linking unique Aadhaar Card number with Voter I-Card to purify the electoral roll." महोदय, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ने एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार इस बात की अनुशंसा की है कि वोटर आईडी कार्ड के साथ 'आधार' को जोड़ा जाए। ... (व्यवधान) ... इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की 109th Action Taken Report में भी इसका जिक्र है। ... (व्यवधान) ... उसमें सरकार कहती है, "The Election Commission of India has proposed to link the electroral roll with the Aadhaar ecosystem with a view to curbing the menace of multiple environment of the same person at different places. This would require amendments in the election laws. The matter is under consderation of the Government." ... (interruptions) ... महोदय, मैं जनना चाहता हूँ कि जब पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ने सर्वसम्मति ये यह अनुशंसा की, तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, टीएमसी के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? ... (व्यवधान) ... वे आज वैल में आकर एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसको लागू करने के लिए ये सारे लोग शामिल थे। ...(व्यवधान) ...

महोदय, 109th Action Taken Report पर समिति की अनुसंशा थी (व्यवधान) ... It says, "The Committee acknowledges the initiative of the Commission and is of the opinion that the linkage of Aadhaar number with Voter ID card will also bring about transparancy in electroral process. The committee further recommends the Election Commission and the Legislative Department to step up measures in this regard and apprise the

Committee of the output before the consideration of the forthcoming demands for Grants of the Ministry of Law and justice." ... (interruptions) ... महोदय, यह ATR है, जो इस सदन के अंदर रखी गई और जिसमें कमिटी ने यह निर्देश दिया कि जब वर्ष 2022-23 की Demands for Grants की चर्चा होगी, जो उसमें सरकार बताए कि 'आधार' को जोड़ने के बारे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? ... (व्यवधान) ...

जो बिल पेश किया गया है, इसमें कहा गया है कि यह mandatory नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है। ... (व्यवधान) ... It says, "No application for inclusion of name in the electroral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed." यानी, अगर कोई व्यक्ति अपना 'आधार' नम्बर किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं करा सकता है, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा ... (व्यवधान) ... उसका नाम मतदाता सूचि से विलोपित नहीं किया जाएगा। ... (व्यवधान) ... उपसभापति महोदय, इस बिल में इस बात की स्पष्टता है कि वह बाध्यकारी नहीं है, यह mandatory नहीं है, बल्कि यह optional है। ... (व्यवधान) ...

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : जो लोग चाहें, अपना आधार नंबर देंगे, ... (व्यवधान) ... जो लोग अपना आधार नंबर नहीं दे सकते हैं, उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। ... (व्यवधान) ... महोदय, इस बिल के विरोध का कारण यह है कि इनलोगों ने मतदाता सूची में लाखों बोगस नाम जुड़वा रखे हैं। ... (व्यवधान) ... इनके एक आदमी का नाम चार-चार बार है। ... (व्यवधान) ... वंगाल के अन्दर जो सफलता मिली है, वह इस बोगस वोटर लिस्ट के कारण मिली है। ... (व्यवधान) ... अगर ''आधार'' से लिंक कर दिया गया, तो जो लाखो बोगस नाम, फेक नाम हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम को दर्ज करा लिया था, वे सारे नाम हटा दिए जाएंगे। ... व्यवधान ... उन्हें इस बात का डर है और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग इसका विरोध कर रहे है। ... (व्यवधान) ...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY : Sir I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Sukhendu Sekhar Rayji has raised a point of order. ... (Interruption) ... माननीय सुखेन्दु शेखर राय जी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहते है। ... (व्यवधान) ...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY : Secondly, just now, the hon, Member said that यह बेबुनियाद है। ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It will be examined, ... (interruptions) ... it will be examined ... (interruption) ... Please ... (interruptions)

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभापति महोदय, उस समय भूपेन्द्र यादव के चेयनमैन थे। ... (व्यवधान) ... मैंने पूरी verbatin report देखी है। ... (व्यवधान) ... There is no note of dissent from Sukhendu Sekhar Rayji. Nobody has given any note of dissent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please speak on the Bill. माननीय मोदी जी, आपके पास केवल एक मिनट और बचा है।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, केवल बंगाल में ही नहीं, केरल के अंदर भी वोटर लिस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बोगस नाम दर्ज करवा रखे हैं। ... (व्यवधान) ... उपसभापति महोदय, जब यह अनिवार्य नहीं है, mandatory नहीं है, तो फिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ... (व्यवधान) ... ये लोग कहते हैं कि Puttaswamy के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है I would like to quote Supreme Court's direction. "Hon. Supreme Court has since passed its final judgment in the matters relating to the Aadhaar issue. The Commision has considered the matter further in view of the direction, the judgment. The Commission is keen to make use of the Unique I.D. numbers provided by Aadhaar Scheme for cleaning the electroral rolls and errror-free electroral rolls form the basis for credible elections.

श्री उपसभापति : माननीय मोदी जी, आपका समय खत्म हो रहा है। ... (व्यवधान) ... प्लीज, अब आप कन्क्लूड कीजिए। ... (व्यवधान) ...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI : Therefore, It would be in national interest to use Aadhaar numbers for verification purpose to ensure the identity of applicant and to prevent multiple enrolment of same person in the electoral roll."

श्री उपसभापति : प्लीज, आप कन्क्लूड कीजिए। ... (व्यवधान) ... आपका समय खत्म हो रहा है। ... (व्यवधान) ... प्लीज, अब कन्क्लूड कीजिए। ... (व्यवधान) ... आपका समय खत्म हो गया है। ... (व्यवधान) ...

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ... ... (व्यवधान) ... मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति : आपका समय खत्म हो चुका है। ... (व्यवधान) ...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI : In view of the above quoted observation made by the hon, Spreme Court, महोदय, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ... (व्यवधान) ... महोदय, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई आपत्ति नहीं है। ... (व्यवधान) ... सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में यह संशोधन लाया जा रहा है। ... (व्यवधान) ... अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वह समाजवादी पार्टी या सीपीएम ... (व्यवधान) ...

◈◈◈

The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021
पर
राज्य सभा में दिया गया भाषण
(CBI और CVC के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाये जाने सम्बंधी बिल)

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : उप-सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस देश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा। एक मेरे राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री हाल ही में बेल पर छूटे हैं। एक राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री 11 साल जेल की सजा काटकर निकले और एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को भी लम्बे समय तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी देश एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे, जो 13 साल तक गुजरात के मुख्य मंत्री और सात साल से देश के प्रधान मंत्री है। इन बीस वर्षों में न तो उनके ऊपर कोई आरोप लगा और न ही उनकी मंत्रिपरिषद् के किसी भी सदस्य पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा।

महोदय, जब 2019 का लोक सभा चुनाव हो रहा था, तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी पर आरोप लगा कि राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने आरोप लगाया था, उन लोगों को न्यायालय के सामने जाकर माफी मांगनी पड़ी और राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'We are, thus, of the view that the review petitions are without any merit and accordingly dismissed. We do believe that persons holding such important positions in the political spectrum must be more careful. Certainly, Mr. Gandhi needs to be move careful in future.' तो जिन लोगों ने आरोप लगाया था कि सारे मोदी चोर हैं, चौकीदार चोर हैं, उनको जनता ने सबक सिखा दिया था, उनको जनता ने जवाब दे दिया था।

महोदय, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'We would not like to continue these proceedings further and thus close the contempt proceedings with the word of cautions for the contemnor to be more careful of future. These applications do not survive for consideration and the same are disposed of. Any other pending applications also stand disposed."

महोदय, यह कोई सामान्य बात नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में लम्बे समय तक रहने के बावजूद किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। महोदय, ग्लोबल करप्शन की रैंकिंग करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, that is known as TRACE, यह अंतर्राष्ट्रीय बिजनेश एसोसिएशन से जुड़ा एक संगठन है, जो bribery-risk faced by the foreign investors, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको किन-किन देशों में, किस प्रकार भ्रष्टाचार या bribery का मुकाबला करना पड़ा, तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि TRACE के ट्रैक के अनुसार 2014 में जहां भारत 185वें स्थान पर था, वह छह साल में 2020 में, 77वें रैंक पर पहुंच गया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मुकाबला किया, यह उसका परिणाम था।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पिछले सात वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी हैं - उन्होंने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा और यह भी कहा कि न मैं किसी को छेडूगाँ और न किसी को छोडूगाँ - इसीलिए हमने किसी को भी जान-बूझकर छेड़ने का काम नहीं किया है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार में, लिप्त होगा, तो सरकार उसको छोड़ेगी भी नहीं।

महोदय, हमारी सरकार की मंत्रीपरिषद् की पहली बैठक में SIT का गठन किया। SIT का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तीन वर्षों से था। मैं यूपीए के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, तो आपने तीन साल तक SIT का गठन क्यों नहीं किया? जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी तब मंत्रीपरिषद् की पहली बैठक में, पहला निर्णय SIT गठित करने का था, जिससे कि ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

महोदय, पिछले सात वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किया है, मैं उसी संदर्भ में बताना चाहता हूं कि Mauritius, Cyprus, Singapore ऐसे देश थे, जिनके माध्यम से India में black money route होता था। यहाँ की सरकार ने कानून बनाया, ताकि Mauritius, Cyprus, Singapore से आनेवाले black-money को रोका जा सके। इन देशों से आने वाले black money को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया। इतना ही नहीं, अगर भारत के किन्हीं लोगों का स्विट्जरलैंड या यूरोप के देशों में bank account में पैसा है या उन देशों के लोगों का हमारे bank account में पैसा है, तो हमने एक समझौता

किया – Real time transaction data with switzerland and other European countries, ताकि दुनिया के यूरोपीय देशों के बैंकों में भारतीयों का जो पैसा जमा है उसकी real-time जानकारी मिल सके।

महोदय, benami transaction का कानून यूपीए की सरकार के समय बना परंतु उसको लागू नही किया गया। Benami transaction कानून को श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लागू करने का काम किया।

महोदय, political funding का प्रावधान था कि 20 हजार रूपये नकद दिया जा सकता है। परंतु, हमारी सरकार ने कानून बनाया कि किसी भी पार्टी को दो हजार से ज्यादा नकद नही दिया जा सकता है।

महोदय, चाहे वह नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्य हो, हमने ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए कानून बनाया। Fugitive Economic Offenders Bill to empower law enforcement agencies to confiscate the assets of economic abssconders. जो लोग इस देश का, बैंकों का पैसा लेकर भाग गए, उन्हें वापस लाने के लिए, उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए हमने Fugitive Economic Offenders Bill लाकर उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम किया है। महोदय, यह है नरेन्द्र मोदी की सरकार।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के दौरान हुए Coal block आवंटन को रद्द कर दिया था। उनके जमाने में नियम था, fist come, first serve यानी पहले आओ, 'पहले पाओ'। इसका क्या परिणाम हुआ? उस सरकार के कितने लोगों को जेल जाना पड़ा था। हमारी सरकार के आने के बाद Coal blocks का online auction किया गया, जिसके कारण इस देश को 5 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का लाभ हुआ है।

महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है, मेरे पास 21.5.2021 तक का आंकड़ा है कि Black Money Act. 2015 has been passed and in 166 cases, demand of Rs. 8.216 crores has been raised. ब्लैक मनी एक्ट सिर्फ बनाया ही नहीं गया, बल्कि बनाने के बाद 166 मामलों में 8,216 करोड़ रूपये टैक्स की उनके खिलाफ डिमांड रेज़ करने का भी काम किया है। Undisclosed income of Rs. 8,465 crores has been brought under tax and a penalty of Rs. 1,294 crore has been levied in HSBC cases.

महोदय, Undisclosed income of more than Rs. 11,000 crore has been detected in International Consortium of Investigative Journalist cases. अभी हाल के दिनों में एक अखबार ने Panama and Paradise Paper leaks को उद्घाटित किया था और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि in the Panama Paper leaks cases an undisclosed credit of Rs. 20,078 crore has been detected. In the Paradise Paper leaks cases, an undisclosed credit of Rs. 246 crore has been detected.

महोदय, इस सरकार ने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की।

महोदय, हमारी सरकार ने केवल बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की, अपितु जो गाँव का सामान्य आदमी हैं, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम' के माध्यम से पैसा भेजकर इस देश के more than Rs. 2,67,000 crore of money has been saved, जो कि बिचौलियों, मिडिलमैन के पास चले जाते थे। लेकिन हमने 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम' के इस माध्यम से इस देश के गरीबों के 2 लाख, 67 हजार करोड़ रूपये बचाने का काम किया है। महोदय, इस 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम' के माध्यम से अभी तक कुल 19,75,000 करोड़ रूपए इस देश के गरीबों के खाते में ट्रांसफर किये जा चुके है।

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : महोदय, सबसे ज्यादा लीकेज पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में था। देश में चार करोड़ से ज्यादा बोगस, फेक और डुप्लीकेट राशन काड्र्स को रद्द किया गया और 1,10,000 करोड़ रूपये की बचत केवल पीडीएस के माध्यम से हुई है।

महोदय, इसी प्रकार गैस कनेक्शन के अंदर भी काफी घपला था। एक व्यक्ति को एक गैस कनेक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन बड़े लोग पांच-पांच, छह-छह, एक-एक दर्जन गैस कनेक्शंस रखते थे। डीबीटी के माध्यम से 4 करोड़, 11 लाख से ज्यादा फेक और डुप्लीकेट गैस कनेक्शंस को रद्द करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस कारण से इस देश को 72,000 करोड़ रूपए की बचत हुई है।

इसी तरह से scholarship में करीब 24 लाख fake scholarships बच्चों को जा रही थीं, उसे रोकने का काम हुआ है। जहां तक खाद की बात है, अगर आज कोई फर्टिलाइजर की दुकान पर जाता है, पीडीएस की दुकान पर जाता है, तो वहां POS machines लगी हुई हैं। आपको उस पर अपना finger लगाना पड़ेगा, उसका biometric identification होगा, उसके बाद ही वह फर्टिलाइजर ले सकता है, करीब 10,000 करोड़ रूपये की बचत इस माध्यम से हुई है।

महोदय, लोग कहते थे कि इस देश में गरीबों का खाता कैसे खुलेगा, उनके खाते में डीबीटी कैसे जाएगा? इस देश में प्रत्येक गरीब को जो 'मनरेगा' के beneficiaries हैं, उनका एक-एक पैसा उनके बैंक खाते में जा रहा है। देश को 33,475 करोड़ रूपए की बचत केवल 'मनरेगा' के डीबीटी के कारण हुई है। 'पेंशन योजना' में 10 लाख से ज्यादा बोगस और फेक beneficiaries को पकड़ा गया। उसी प्रकार Women and Child Development Programme में एक करोड़ से ज्यादा fake beneficiaries detect किए गए।

महोदय, सीबीआई, सीवीसी और ईडी के बारे में तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जब तक नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नही और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह हमारी केन्द्र की सरकार हो या हमारे राज्यों की सरकारे हो।

महोदय, अच्छा होता यदि विपक्ष के लोग सदन में मौजूद रहते। उन्हें भी सत्ता में रहने का मौका मिला, वे भी बताते है कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट बताया है कि सीवीसी और जो स्पेशल पुलिस एक्ट सीबीआई कानून में संशोधन कर कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है, तो उसे केवल सरकार अकेले नहीं बढ़ा सकती है उसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ दि अपोजिशन, ये तीनों मिलकर निर्णय करेंगे। जब इनकी सहमति बनेती तब ही उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

उप-सभापति महोदय, मैं इस बिल को लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

◈◈◈

DEMAND FOR SCRAPPING MEMBERS OF PARLIAMENT EXCLUSIVE QUOTA FOR ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYA

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, केन्द्रीय विद्यालयों के अंदर एमपीज़ का जो कोटा है, मैं उसको समाप्त करने की माँग करता हूं। ... (व्यवधान) ...

उप-सभापति महोदय, there are more than 788 MPs, and each MP has 10 seats ... (interruptions) ...

MR. CHAIRMAN : Please go to your seats ... (interruptions) ... Please go to your seats. ... (interruptions) ... Do not test the patience of the country. ... (interruptions) ... Do not test the patience of the country. ... (interruptions) ...

श्री सुशील कुमार मोदी : उनकी अनुशंसा पर 10 बच्चों का नामांकन केन्द्रीय विद्यालयों में किया जाता है । ... (व्यवधान) ...

MR. CHAIRMAN : Do not test my patience as well as the patience of the country ... (interruptions) ...

श्री सुशील कुमार मोदी : इस प्रकार, जो 7,800 seats हैं, उन पर एमपीज की recommendation से नामांकन दिया जाता है। ... (व्यवधान) ... इसमें किसी प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ... (व्यवधान) ...

श्री सुशील कुमार मोदी : इस तरह, हम 4,000 से ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों को नामांकन से वंचित करते हैं। ... (व्यवधान) ... मैं माननीय मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कोटा समाप्त करने का निर्णय लिया है। ... (व्यवधान) ... Sir, it goes against the spirit of democracy, transparency and meritocracy ... (Interruptions) ... अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IITs में, IIMs में एमपीज को अधिकार नहीं है, तो क्या कारण है कि उन्हें केन्द्रीय विद्यालयों में यह अधिकार दिया गया है? ... (व्यवधान) ... उनका नवोदय विद्यालय में भी कोई अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान) ... सर, एक-एक एमपी के पास हजार-हजार, दो-दो हजार लोग recommendation के लिए आते हैं, जबकि वे केवल 10 लोगों को ही खुश कर पाते हैं, जिसके कारण एम्पीज के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ... (व्यवधान) ... सभापति महोदय, इसमें Transparency होनी चाहिए।

सर, मैं यह माँग करता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए एमपीज का जो 10 सीट्स को कोटा है, उसको तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और ये सीट्स open merit पर छोड़ देनी चाहिए, ताकि जो गरीब और समान्य बच्चे हैं, वे इसका लाभ उठा सकें। ... (व्यवधान) ... मैंने बड़ी संख्या में एमपीज से बातचीत की और अधिकांश एमपीज चाहते हैं कि यह कोटा समाप्त कर दिया जाए। ... (व्यवधान) ...

श्री सुशील कुमार मोदी (क्रमागत) : सभापति महोदय, वर्ष 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कोटे को समाप्त कर दिया था, लेकिन वर्ष 2000 में फिर से प्रारम्भ हो गया। ... (व्यवधान) ... वर्ष 2010 में जब श्री कपिल सिम्बल जी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन वह फिर प्रारंभ हो गया। ... (व्यवधान) ... महोदय, हर केन्द्रीय विद्यालय के चेयरमैन का भी दो सीट्स का कोटा है, उसी प्रकार मंत्री का कोटा है। ... (व्यवधान) ... माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जो 7,880 सीटें एमपी के कोटे में हैं, उनको तत्काल समाप्त किया जाए।

◈◈◈

DEMAND FOR DIRECTING SOCIAL MEDIA COMPANIES TO ALLOCATE SPECIFIC BUDGET TO FLAG PROBLEMATIC CONTENT ON THEIR PLATFORM AND ITS REMOVAL

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (BIHAR) : Sir, Google and Facebook together take away around 75 per cent of the total digital advertising market in India. With ad revenues of Rs. 23,213 crores, Rs. 9,326 crores of Facebook and Rs. 13,887 crores of Google, they earn a share higher than the combined revenues of the top 10 listed traditional media companies, at Rs. 8,396 crores. ... (Interruptions) ... Through their Advertisment Reseller model. they send away the major portion; the Facebook sends 90 per cent of gross advertisement revenues to the global subsidiary, while the Google India pays 87 per cent. The issue is that these big tech firms are getting rich at the expense of tradtional media. ... (interruptions) ... Then, it does not pay traditional news platforms, sufficiently despite making huge money by displaying their journalistic content. ... (interruptions) ... To ensure this, following an EU directive, countries like France, Germany and Austrailia have already legislated neighbouring rights in which platforms like Google are made to pay traditional media outlets for use of their content. ... (Interruptions) ...

Sir, Facebook is undermining safety of the largest user base of 34 crores in India. It does not flag problematic content like fake, misinformation and hate speech. As per a report, Facebook found that over 40 per cent of top views in the State of West Bengal were 'fake/unauthentic'. .. (Interruptions) ... Even on the death of Shri Bipin Rawat, there were objectionable tweets on Facebook and other social media platforms. The facebook spends a miniscule just 13 per cent of its budget to flag content in market outside the US. ... (Interruptions) ... Thus, the percentage of budget which gets allocated to India is even less than 13 per cent. It lacks capacity to flag content for Hindi and Bengali. Recently, even the PM's account was hacked by crypto lobby bringing out a tweet declaring that India has 'officially adopted Bitcoin as legal tender'. ... (Interruptions) ... I would, therefore, urge that India

must form an independent regulat4ory body that ensures a legislative framework which shall oversee the activities of these Big Tech Companies and also ensures that these platforms dedicate proper budgetary allocation towards 'content moderation' and 'revenue sharing' with traditional media. ... (Interruptions) ... Sir, with these words, I, again, urge that the Government of India should take action against these social media giants. Thank you.

◈◈◈

DEMAND FOR REGULATING ONLINE GAMING INDUSTRY

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (BIHAR) : Sir, I am raising the issue of online gaming. The booming online gaming has become a big problem for the youngsters in this country and crores and crores of youngsters have become addictive to this online gaming. Because it is online, it is very difficult to prevent the kids to become addictive to the online gaming and now this online gaming has been converted into gambling or betting.

Now there is a controversy that as to whether it is a game of skill or a game of chance. I would like to tell the House that during pre-Covid, weekly time spent on mobile gaming was 2.5 hours and 11 per cent of total smartphone time was spent on gaming. During lockdown, it increased from 2.5 hours to 4 hours and as on today, more than 43 crore people are using online gaming. इस बात का projection है that by 2025, this will increase to 65.7 crores. The revenue earned was Rs. 13,600 crores from online gaming which is likely to increase to Rs. 29, 000 crores in the year 2025. In India, the number of mobile games downloaded in the first quarter of pre-COVID was 1.86 billion and it increased to 3 billion during the third quarter of 2020. Sir, States banned this online gaming, but it was stuck down from the High Courts. There are games like Ludo which we played when we were young. Now crores and crores of people are playing the Ludo King along with Rummy, Poker, MPL., Dream11 based on cards.

सभापति महोदय, यह जो online हैं, यह बहुत बड़ा addiction बनता जा रहा है। I would like to highlight that the sector like the crypto Industry certain has a regulatory lacuna. I would urge upon the Government of India for uniform tax on online gaming. That is number one. And number two, I urge upon the Government to make a comprehensive framework of regulating online gaming. अगर इस प्रकार का कोई resolution बनता है तो ठीक है, नहीं तो इस देश के करोड़ों बच्चों को हम online की आदत से बचा नहीं पाएंगे।

MR. CHAIRMAN : Whoever wants to associate, they can send their names.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (BIHAR) : Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (ODISHA) : Sir, I to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (WEST BENGAL) : Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI MAUSAM NOOR (WEST BENGAL) : Sir, I to associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI DEEPAK PRAKASH (JHARKHAND) : Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA) : Sir, I too associate myself with the isue raised by the hon. Member.

SHRI K.G. KENKE (NAGALAND) : Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI Y.S. CHOUDHARY (ANDHRA PRADESH) : Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SURESH GOPI (NOMINATED) : Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (MAHARASHTRA) : Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (ODISHA) : Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MUZIBULLA KHAN (ODISHA) : Sir, I too associate myself with me issue raised by the hon. Member.

DR. KANMOZHI NVN SOMU (TAMIL NADU) : Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABDUL MAHAB (KERALA) : Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (ASAM) : Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANAND SHARMA (HIMANCHAL PRADESH) : Sir, I to associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VAIKO (TAMIL NADU) : Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (TAMIL NADU) : Sir, I to associate myself with the matter raised by the hon. Member.

◈◈◈

"DEMAND FOR REGULATION OF 'WORK FROM HOME' IN PRIVATE SECTOR

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESHWAR KALITA) : Now, Shri K. Somaprasad; not present. Shri Jawahar sircar; not present. Shri Sushil Kumar Modi.

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (BIHAR) : Sir, the pandemic necessitated remote work for many industries in the country and going forward, even post pandemic, work from home in hybrid work models is likely to persit.

However, this increasingly normalized phenomenon has evolved totally unregulated. Employers and employees went about working without any formalized and mutuality- decided set of working hours and other conditions.

This led work-hours to spread over an employee's entire day, unrestrained and made work time and home time practically indistinguishable. This has taken a toll as employees experience burnout symptoms making them susceptible to exhaustion and other physical and mental conditions.

Besides, with schools being closed and families getting sick in the health crisis, households needed more tending to, as employees shouldered additional responsibilities being a full-time teacher to their children or caring for the family.

Employees also have to bear additional costs of setting up the digital infrastructure including power backups, laptops, internet and other devices.

It is, therefore, critical that the Government formally regulates 'work-from-home' to safeguard the welfare of workers by protecting their salary, their off-clock hours and compensating them to additional expenses related to remote work. This is needed to provide to legal backing to employees and ensure accountability on the part of the employers.

Countries like Portugal has legislated rules to ensure that the employers pay part of electricity and internet bills, do not interrupt workers post designated office hours except in emergencies of its employees working from home. I urge upon the Government of India to formulate regulations regarding WFH at the earliest.

◈◈◈

Cryptocurrency सम्बंधी पूछे गए प्रश्न का उत्तर

Q. Nos. 19, 23 and 30 (Contd.)

श्री सुशील कुमार मोदी : माननीय उपसभापति महोदय, अभी मैंडम ने advertisements के बारे में बताया। I want to ask Madam that in the last four months; there were a flurry of misleading ads in the TV, print media and social media which were promising heaven to the investors. During the World cup 2020, more than Rs. 50 crores were spent by crypto exchange companies क्योंकि RBI के जो statements आये हैं, उन्हें किसी ने पढ़ा नहीं हैं। वे statements केवल अंग्रेजी के अखबारों में आये हैं are you going to insert advertisements prominently in all the regional, Hindi and English newspapers?

My second question: Since these ads are without any disclaimer, is the Government of India thinking of banning such advertisements which are misleading और जिसके कारण लोगों को करोड़ों रूपयों का नुकसान हो सकता है? इसलिए मेरा यह Specific question हैं कि is the Government of India contemplating to ban such misleading advertisements till the Bill comes to this House? I am asking because nobody knows whether this Bill will come or not. Last time also it was mentioned in the Bulletin, but it could not come into the House. इसलिए मेरा आग्रह है कि क्या सरकार इनको ban करने के बारे में विचार करेंगी?

SHRIMATI NIRMALA SITARAMAN : Sir, there are two things, Last time also there was a Bill proposed and then it didn't happen. I just want to remind the hon. member that yes, last time there was a Bill proposed, but subsequently, because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the Bill, that Bill has been re-worked and in a way the Bill which a coming now is a new Bill. But never mind, the work done on that have all been taken or board here. So, the intent was either we improve that Bill or come with a Bill which is going to be far more recent. So, the intent of getting the Bill at that time was there. It was a genuine intent. Now we are coming up with a new Bill. So, It is not as if last time we just put it there

and didn't want to come with one and so leading to suspcion that this time also we are putting a Bill and we may not come up with one. No, let me be clear on that. The earlier attempt was definitely to come up with the Bill, which the House can consider. But later, because rapidly a lot of things had to come into play, we started working on a new Bill and this is the Bill which is now being proposed. Once the Cabinet clears the Bill, it will come here before the House. That is one thing.

The second thing is about the misleading advertisements and whether we are banning them. I want to inform the hon. Member who has been a finance Minister earlier in Bihar and has also been in a very influencial and guiding positions in the GST Council whose advise all of us have benefited from. So, I value his question. There are with the Advertising Standards Council of India, the ASCI, which governs on advertisments. Their guidelines are being studied and the regulations that they have are all being looked into so that we can take, If necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the hon. Member.

SHRI SUSHIL KUMAR MODI : Sir, my second question is regarding Government seeking to make a separate legal framework for NFT, It has not been replied in this answer. So I would like to know about it because there should be a separate legal framework for NFT. It should not be a part of Crypto Currency Act. So, (1) is the Government thinking of a separate leagal framework for NFT; and (2) because you have answered in (d) part of the question. I would like to know how many people have paid income tax on cryptocurrencies and how much tax has been collected?

SHRIMATI NIRMALA SITARAMAN : Sir, I don't have the ready information as to how much tax has been collected on cryptocurrency or how much has been paid on it.

As regards NFT (Non-Fungible Token), hon. Member desires to have a separate legal framework. At this moment, I may not be able to say whether I will give a separate framework or not. But, certainly, as I said, all these matters are being discussed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Q No. 20. Hon. Member not present. Any supplementary?

India's Inflation Story

Sushil Kumar Modi
MP, Rajya Sabha
Ex. Dy. CM, Bihar
(***The Economic Times*** मे प्रकाशित लेख)

Inflation pinches a citizen more than any other economic phenomenon. After the pandemic's second wave, economic and political thinkers worldwide are still vacillating between whether this is transitory or structural. Amid this din, India's experience has been better than rest of the developed world and its own previous experience, after the Global Financial Crisis.

Post pandemic inflation has started festering as a worldwide phenomenon. In US, it rose to a 39 year high of 6.8%, the European Union witnessed a 30-year high headline inflation of 4.9% (more than twice the ECB's targeted 2%). Other countries are gripped by runaway inflation such as Argentina (50%), Turkey (20%), Brazil (10.67%) and Russia (8.1%). However, the Indian experience of inflation evinces silver linings. It is much restrained, with headline inflation at 4.9%, remaining well within the RBI targeted band for the fifth month in a row, and reflects swiftly recovering demand signalling prospects of higher growth in the long run.

There has been a host of factors responsible for the worldwide price increases; from shipping container crises to global crude oil inflation. This international inflation inevitably gets imported and translates into domestic inflation because India is highly linked with the global economy and relies on global value chains for its economic activities.

Inflation is the outcome of both supply and demand mismatch hence policy measures must focus on both. Only demand-side interventions, although increase demand in the short run, risk leaving overhangs of persistent inflation. The experience of countries which went into spending overdrive focusing only on stimulus has proven this, as big spenders were more susceptible to higher inflation, interest rates and currency depreciation, offsetting the benefits from stimulus. India's policy response was well-calibrated in this sense. It could revive output while also containing inflation by sustaining demand and enhancing supply.

During the '08 crisis, under the UPA-2 regime, India suffered 10.42% of average inflation rate from 2008-13. Inflation had crossed 9% in 22 out of the 28 months from Jan 2012 to April 2014 and this happened despite there being no lockdowns or supply chain disruptions. To put this into perspective, inflation during the NDA years of 2014-20 was 4.8%, because

the government implemented the “Inflation Targeting Regime”, wherein the RBI was mandated to ensure inflation within 2-6% band.

The recent inflationary pressures have been driven mainly by fuel and edible oils. A large part of this is not due to domestic reasons but international supply issues. However, the slew of measures taken are softening the blow.

India is heavily reliant on imports of crude petroleum and edible oils, meeting 83% and 60% of their respective demands through imports. International petroleum prices rose in an accelerated manner from $20/bbl to $83/bbl after the pandemic struck as oil producing countries artificially reduced supply level, distorting market prices.

This creates a double whammy: it not only raises India's import bills as it has to ensure procurement through forward-contracts, but also hazards indirect inflation in the economy.

To mitigate the adverse impacts, the government has cut petrol excise duty by Rs 5/litre and diesel duty Rs10/litre. With this, the Centre shall forego 8,689 crores monthly. This will translate into an annual benefit of 1.04 lakh crore channelized to the common people in the form of reduced prices. Unfortunately, 7 non-BJP states have still not reduced their VAT impositions but have only tried to score brownie points by putting the central government in the dock for rising inflation.

India agreed to release 5 million barrels of strategic reserves, coordinating with global energy consumers including the USA, China, and Japan. As a long-term measure, the government has also undertaken ethanol blending program to reduce import dependency and weather adverse price shocks.

In the brouhaha around fuel prices, most commentators overestimate its financial impact because the expenditure on fuel is a miniscule percentage of a common person's budget as reflected in their weightage in India's headline inflation basket: merely 2.19% and 0.15% for petrol and diesel respectively.

These weightages are assigned in accordance with households' consumption expenditure, hence reflect the impact on common citizens better than the wholesale inflation or WPI which tracks bulk goods sold between businesses. The two indices are clearly distinct in their purpose and weightage of their constituents.

The sharp uptick in WPI, averaging over 12% from April to November'21 reflects input-side price pressures faced by wholesale businesses and the basket's high numbers were driven by weighty categories of fuel, power and metals. But, even the indirect effects operating through fuel and transportation costs have been tepid as there is still slack in the economy and pass-through inflation has remained muted.

Prices of food items significantly impact households. Food inflation averaged only 2.8% from April to November 21, compared to 9% during UPA, hitting as high as 27% in 2010. To further lessen the impact, the government has provided free ration to 80 crore beneficiaries for the past 19 months, worth Rs 2.6 lakh crores, and shielded the vulnerable sections.

Although there has been an uptick in the latest inflation figures, it was because food (mainly vegetables) inflation has outpaced the moderation achieved in edible oil and fuel prices. However, it's only expected that after the second wave, pent-up and rallying demand conditions amid rebounding economic activities, coupled with an unfavourable base in coming months would cause inflation figures to rise. Going forward, this would get subdued when the hike in vegetable prices will self-correct due to a strong Rabi output.

Droughts and labour shortages in edible-oil exporting countries inflated India's import bills and retail prices of the same. To ease prices, basic duties on palm, soyabean and sunflower oils have been slashed to zero. Even Agri-cess was reduced by 12.5% - 15 %. To curb artificial scarcity, stock limits and ban on mustard futures trading have been imposed. Consequently, wholesale prices fell by 7-11% across categories. As a long-term measure, by investing ₹11,040-crore under the National Mission of Edible Oils, the government is increasing the acreage of edible oil to reduce import dependency.

Strong supply-side interventions ensuring adequate liquidity, relief packages and production incentives to industry players have caused 19 out of the 22 high-frequency economic indicators like e-way bills, exports, coal production, freight traffic etc. to rebound fully and even exceed pre-pandemic levels. Moreover, highly volatile fuel prices are likely to soften after hitting peaks and fuel inflation has already started moderating from an all-time high of 14.3% in October to 13.3% in November.

Thus, India's management of the inflationary risks has been better than other countries and the previous crisis when quantitative easing was the primary tool relied upon by countries. With a focus on reform rather than mere spending, well-calibrated policy to expand capacity through CAPEX and schemes to mitigate the pains, there's much to be appreciated in India's inflation experience and the emerging green shoots in the economy.

Gaming Versus Gambling

Sushil Kumar Modi
MP, Rajya Sabha
Ex. Dy. CM, Bihar
(***The Indian Express*** मे प्रकाशित लेख)

Of the numerous things that the pandemic has changed in our lives one very obvious one is the way we entertain ourselves. Amidst the proliferation of OTT channels and the significant rise in viewing hours what has gone unnoticed is the burgeoning usage of online gaming. The average time spent on online gaming went up almost 65% from the pre-covid levels. More than 43crores people have spent time on virtual gaming. Before we get into the implications of this change it is important to understand what is online gaming.

There are typically 3 types of online gaming. The first, e-sports are video games which in the 1990s was played privately or on consoles in video game shops but are now played online in an organized way between professional players, individually or as teams. Second, fantasy sports are games in which you choose a team of real sports players from different teams and win points according to how well the players perform in real life. Finally, online casual games could be skilled-based – where the outcome is predominantly influenced by mental or physical skill; or those based on chance where the end result is strongly determined by some randomized activity such as rolling the dice. A game of chance may be considered as gambling if players wager money or anything of monetary value.

This flourishing industry however suffers from a complex jumble of regulatory oversight. Online gaming falls in the regulatory grey area and there exists no comprehensive legislation with respect to its legality, or its boundaries with gambling and betting even as the applicable tax rate is being debated in relevant circles.

From this definitional issue flows the legality of online gaming. Games based on skills are allowed in most parts of the country while games of chance are in the ambit of gambling and are treated as immoral and illegal and are largely prohibited throughout the country. As betting and gambling is a State subject as per the Constitution different states have their own legislation. As it stands, every state in India, except Goa, Sikkim, and the Union Territory of Daman explicitly prohibits any sort of gambling, betting or wagering on games of chance. The states of Assam, Andhra Pradesh, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, and Telangana have placed

restrictions on games of skill as well. Online games based on the traditional Ludo, arguably the most popular online games in India have run into controversy having been accused of betting and gambling.

Notwithstanding the legal position, a large number of people are developing a strong dependence on online gaming. This addiction is destroying lives and devastating families. Online gaming can possibly take proportions of social evil. Compulsive usage of technology was heading towards becoming an issue and the pandemic managed to catalyse the steady journey. It has caused a dramatic increase in our screen time.

Parents across the country are struggling – without much success – to help their children set limits around technology usage and gaming. Young boys and girls are trapped into compulsive gaming, many spending as much as 6-8 hours per day playing online games. This is affecting their performance in school and at work and their social lives and relationships with family members often become strained.

Psychologists have opined that the opportunity cost of this is immense as the impact on health is growing with each passing day. It is worth noting that online games like PUBG and Blue Whale Challenge were banned after incidents of violence and suicide. This addiction is also said to be causing near-sightedness in our youth. Further, inadvertent sharing of personal information can lead to cases of cheating, privacy violations, abuse, and bullying.

There is a need to build in checks and balances to prevent the youth from becoming pathological gamers. Various High Courts have nudged state governments to regulate the virtual gaming landscape. Even the central government, in an advisory sent to states recently, has laid out useful dos and don'ts to educate parents and teachers. Even casinos do not allow underage participants hence there is no reason why online gaming companies should be lax about it. Incidentally, the Chinese, as is their wont, have announced rules to limit to three hours a week of online video games for those under 18. The Chinese state media has called online gaming the "opium of the mind."

A well-regulated online gaming industry presents compelling advantages in terms of the economic benefits too. This industry is expected to generate revenues in excess of Rs29000 crores in 2025 with over 65.7crore users. It is estimated that more than 15000 direct and indirect jobs will be created. A Group of Ministers (GoM) of the GST council is seized with the matter of fixing the rate for online games. The debate between a GST rate of 18% for

games of skill and 28% for games of chance is expected to be settled soon. The GST and Income Tax generated from this industry will add to the economic multiplier. This sector has the potential to attract significant global investments; current investments in gaming companies like Dream11 are good indicators.

There is an urgent need to emerge from this muddle and regulate this industry suitably. A comprehensive make-over will have far-reaching benefits. The government should ensure that KYC norms are strengthened. Each game should follow a well-established age rating mechanism and minors should be allowed to proceed only with the consent of their parents – OTP verification on Aadhar could potentially resolve it. No in-game purchases should be allowed without adult consent and wherever possible in-game chat option should be disabled. Gaming companies should proactively educate users about potential risks and how to identify likely situations of cheating and abuse. They should remove the anonymity of all participants and build a robust grievance handling mechanism.

A Gaming Authority at the central government should be created while various forms of self- regulation are encouraged for the industry. This authority could be made responsible for the online gaming industry, monitoring its operations, preventing societal issues, suitably classifying games of skill or chance, overseeing consumer protection, and combatting illegality and crime.

Tyranny of the Opposition

Written by Sushil Kumar Modi
Ex-Deputy Chief Minister of Bihar
Member of Parliament, Rajya Sabha
(*The Times of India* मे प्रकाशित लेख)

Picture a gathering where security personnel, including women staff, are manhandled, an attempt to strangulate another security personnel takes place, somebody pulls, drags and even threatens them, somebody else tries to climb the LED TV stand, another person jumps on the table, others whistle, hoot and heckle, and another set of people posture to assault the group of people who are going about their job purposefully and there is a sense of competition amongst members for the kind of nuisance that can be created. You would expect this to be a scene from some conclave of rowdies but this however is a collection of recent events from the Parliament.

The RajyaSabha has been disrupted for many days in the current winter session too primarily due to the suspension of 12 members for their behaviour on the last day of the monsoon session in August 2021. During the same session besides scenes of street anarchy described above, for the first time ever the PM was prevented from introducing newly sworn-in ministers. Papers were snatched from a Minister, torn into pieces and flung at the Chair. An MP paraded in the house with a mock noose tied around her neck while the second tugged the loose end and another MP broke the glass pane of the door. On many occasions, some MPs have hindered the participation of others in discussions by blocking their view and by flashing placards. Some other members proudly informed the media about their stunts. Wearing their despicable behaviour as a badge of honour is no better than that of a not so well brought up juvenile.

The Leader of the House proposed a special disciplinary committee to identify the guilty and decide the punishment as per the rules. Members from the opposition balked – exposing their mal-intent. Inspite of repeated requests by the government to allow the smooth functioning of the house the opposition parties have consistently refused to acquiesce. Even for the pre-agreed agenda, the opposition refused to work with the government as if the primary objective was to achieve a total washout of the session. The suspended members and their leaders are yet to express regret for their riotous behaviour. Paradoxically they are on a sit-in by the statue of one of the greatest self-disciplinarian, the Mahatma.

Informally, MPs at large are desirous of debate and discussion they however are guided to paralyse Parliament by their respective leaders,

hence this unrelenting chaos. Below the surface of this behaviour is the inability of party leaders to reconcile with an immensely popular democratically elected government that doesn't revolve around them. This probably is the primary reason why the opposition has failed to behave constructively.

Often, BJP's protests, trooping in the well and walkouts are cited but that is a misplaced comparison because there has never been an incidence of a BJP member turning violent, or snatching papers or breaking microphones.

The current saga of disruptions started on 20th September 2020 when the House was seized with the Farm Bills. After almost 4 hours of discussions involving 33 participants, the opposition parties resorted to chaos, which was re-created during the last monsoon session**,** with the sole purpose of preventing the passing of the bill. It was an attempt at what can be called the 'tyranny of the minority'. In the last monsoon session, 76 hours were lost due to such disturbances. Unfortunately, these interruptions have continued till date.

Those who are accusing the BJP of rushing through with bills must take note that during the UPA government, 24 bills were passed in the din without any discussion. There were many instances during that regime where protesting MPs were suspended to enable the passing of bills, for instance, the Andhra Pradesh Reorganisation Bill where the protesting MPs were evicted from the house using force. Even during the 9thLokSabha (1991-96), the Congress government passed 18 bills without any discussion in less than cumulative 2 hours.

It is a fallacy that bills are not being scrutinised because with the implementation of the pre-legislative consultation policy, 2014 all proposed legislation is released in the public domain (for at least 30 days) with the express purpose of obtaining objections and suggestions from a wide range of stakeholders hence going through extensive analysis.

Needless to say, disruption and violence lower the dignity of the Parliament and this shameless behaviour has made a mockery of our democracy. Therefore there is a need to rise above narrow interests and work with the popularly elected government to offer to the people of India a Parliament they can look up to. The government is keen to go about its legislative activities in an orderly fashion but to be held hostage by few troublemakers will be akin to the shirking of responsibilities. The government is duty-bound to stretch every sinew to help India progress.

Whither Cryptocurrency

Sushil Kumar Modi
RajyaSabha MP,
Ex. Dy. Chief Minister of Bihar
(***The Economic Times*** मे प्रकाशित लेख)

June was a typical month for cryptocurrencies – significant volatility in prices along with new elements of acceptability when tiny Central American country El Salvador declared Bitcoins, a leading cryptocurrency, as legal tender. While maverick tech leader Elon Musk managed to create grotesque swings in the value of cryptocurrencies by merely tweeting, the recent price fluctuationshave been underpinned by regulatory action across many countries. From China to the UK crackdowns have turned the market bearish. World's largestcryptocurrency exchange Binancewas forced to cease operations in the face of these actions.

In India the cryptocurrency ecosystem is in the throes of constant flux. Since 2013 RBI has been warning of the potential risks of the use of cryptocurrencies. In April 2018, the RBI issued a circular banning regulated financial institutions from providing services to businesses dealing with cryptocurrencies. RBIhas regularly cautioned against risks such as that to consumer interests, protection of market integrity, a threat to the credit system, money laundering, and use in terrorism finance. In 2019 an Inter-ministerial committee released a report recommending the banning of private cryptocurrenciesamong other things. The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021to create a digital currency and simultaneously ban all private cryptocurrencies was prepared basis this report and is currently somewhere betweenthe executive and the legislature.

In 2020 the Supreme Court in *Internet and Mobile Association of India (IAMAI) v. Reserve Bank of India* struck down the RBI circular of April 2018 proscribing any services to cryptocurrency players. However, as recently as March this year in a reply to a question raised in Parliament the junior Minister of Finance highlighted that in the Budget Speech of 2018-19 it was stated that 'The Government does not consider cryptocurrencies legal tender or coin and will take measures to eliminate use of these crypto assets in financing illegitimate activities or as part of the payment system. The Government will explore use of block chain technology proactively for ushering in digital economy.'

Clearly, there exists a regulatory vacuum for participants in the industry and this has led to the proliferation of cases of illegality. Very recently the Enforcement Directorate (ED) issued a show-cause notice to WazirX – India's largest crypto exchange – for facilitating money laundering and also for the infringement of the Foreign Exchange Management Act to the tune of almost Rs2800 cr. Similarly the Registrar of Companies (ROC) has issued a notice to Bitcoin India Software Services Ltd, a cryptocurrency wallet based in Andhra Pradesh following large-scale complaints that it had collected over Rs 200 crores from investors and duped them.

IAMAI has set up an advisory board to implement a code of conduct for the industry. Its Blockchain and Crypto Assets Council (BACC)will act as a self-regulatory organisation for the sectorwith the hope to lend it some legitimacy. This,however, might not be enough as the Supreme Court's judgement in the case cited above clearly accepts cryptocurrency as a money-like instrument and establishes that the RBI is the appropriate authority to regulate it. RBI's stance on this has been consistent since 2013. RBI wants to create a robust oversight mechanism. On May 31, the RBI issued a release saying that no bank should quote it's April 2018 circular to reject crypto assets. The same statement also said that there is a need to ensure high-quality compliance with KYC, Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) guidelines.

RBI's issues are underpinned by the dilemma of classification of cryptocurrencies – are they assets, a currency, or a payment system, and can they be slotted as private or public?Will it be possible to achieve a transparent, coherent, and practicable regulatory framework? There are no successful standards as yet across the globe. An accommodative approach in Japan, heavily regulated in the US, practically no regulations in India and many other countries, and, as is their wont, a prohibitive ban in China completes the spectrum.

RBI will also keep in mind cryptocurrency's contribution to the economy. Cryptocurrency doesn't contribute to capital formation just as a stock market investment does nor does it contribute to the exchequer through taxes. Should GST be applicable or an Equalisation Levy may be charged? Another, often, ignored element of cryptocurrencies is the power consumption that the mining process, inherent in blockchain technologies, leads to. According to the Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), Bitcoin currently consumes around 110 Terawatt Hours per year — 0.55% of global electricity production, or roughly equivalent to the annual energy draw of small countries like Malaysia or Sweden. Imagine its impact on the environment.

In parallel, RBI is exploring the option of an official Central Bank Digital Currency (CBDC). The UK also has also set up a task force to study the need for a digital version of the pound sterling. The European Central Bank is also moving towards a CBDC and China has already claimed success of its first pilot project of the digital Yuan. There are more than 50 other countries that are running pilot programs.

Regulatory absence vis a viscryptocurrency does no good for its stakeholders – governments, investors, and even intermediaries. Cryptocurrencies are susceptible to misuse with a far reaching impact on our society. As the number of participants and the value of investments rise fast there is undoubtedly an urgent need to address the regulatory lacuna.

While there may be a case to regulate cryptocurrencies a blanket ban might not be the right path to follow. A ban may not be feasible because the internet cannot be banned; an interested party can anonymously buy through cryptocurrency exchanges abroad using the internet. A ban will only push things underground,create a parallel economy, encouraging illegitimate use, defeating the very purpose of the ban. Blockchain technology is at the core of cryptocurrencies and a ban may stunt potential innovation and development. The government is in favour of this underlying technology and is exploring the enormous possibilities of blockchain for various purposes -data economy, energy, and governance, including keeping land records.

It is high time that the government clears the haze around cryptocurrency. It should use the forthcoming session of Parliament to address it. A first good step will be to firmly categorise cryptocurrencies. Given the regulatory ambiguity across the globe, India should initiate a roundtable to bring in the best minds from all over the world to prepare a multilateral agreement defining global standards.

Till then the Government in conjunction with RBI needs to put together suitable legislation and policy to govern the cryptocurrency industry. Only after the regulatory process is well set should we transition to 'soft touch regulations' so that to allow innovation to thrive and the industry to expand.

''भ्रष्टाचार-करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी ना किसी का हक छीनता है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हों, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है।''

-नरेन्द्र मोदी

" Our constitution is a ray of hope:
H For harmony,
O for Opportunity,
P for people's participation
and E for equality."

- Narendra Modi